मुख्यमंत्री ने त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा की

मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी मंदिर में दर्शन किए

बांसवाड़ा/जयपुर, 25 सितम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को बांसवाड़ा के तलवाड़ा स्थित शक्ति पीठ त्रिपुर सुंदरी मंदिर में दर्शन तथा विधि-विधान से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

- **मुख्यमंत्री ने नापला हैलीपैड पर कहा कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान को जो सौगातें दी हैं, उससे प्रदेश का विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बांसवाड़ा के तलवाड़ा में त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा की।

मंदिर दर्शन से पूर्व मुख्यमंत्री ने नापला हेलीपैड पर मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के प्रति जनता में विशेष आकर्षण, लगाव और विश्वास है, इसलिए इतनी विशाल सभा का आयोजन आज नापला में हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी राजस्थान आते हैं, प्रदेश को सौगातें देते हैं। आज उन्होंने प्रदेश के लिए लगभग 1 लाख 8 हजार करोड़ रुपये के कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। साथ ही, 15 हजार से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वागड़ क्षेत्र में आज माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।

'सरकार मुझे जेल भेजने की तैयारी में है'

लद्दाख, 25 सितंबर। लद्दाख में भड़की हिंसा पर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सरकार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो सरकार की दिक्कतें उनकी आजादी से कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी।

वांगचुक ने गुरुवार को गृहमंत्रालय के उस बयान को खारिज किया जिसमें बुधवार की हिंसा के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार बलि का बकरा तलाश रही है जबकि असली समस्या को नजरअंदाज कर रही है।

भाजपा के सांसदों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जहाँ एक ओर नीतीश कुमार साफ-सुथरे शासन पर जोर दे रहे हैं, वहीं भाजपा की आंतरिक कलह सामने आ रही है, जिससे बिहार में एनडीए का चुनावी गणित काफी कमजोर दिख रहा है। पार्टी नेतृत्व के सामने दोहरी चुनौती है, सहयोगियों को शांत करना और अपने ही वरिष्ठ नेताओं को चुनावी मैदान में उतरने के लिए मनाना। जैसी स्थिति है, एनडीए इस चुनावी मौसम में सवालों से घिरा हुआ है, जवाबों से नहीं।

वांगचुक के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एजूकेशनल एंड कल्चरल मुवमेंट आफ लद्दाख का पंजीकरण प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। उल्लेखनीय है कि सोनम वांगचुक लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने तथा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से हड़ताल कर रहे थे। लेह में बुधवार को हिंसा भड़कने के बाद उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी।

अमेरिका विश्व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह प्लेटफ़ॉर्म युवाओं का ध्यान आकर्षित करने और उन पर प्रभाव डालने में इतना सफल हो गया था कि अमेरिकियों को खतरा महसूस होने लगा और उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की। पूर्व के बाइडन प्रशासन ने कंपनी को आदेश दिया था कि वह अमेरिका में अपनी संपत्तियाँ किसी अमेरिकी समूह को बेच दे। सरकार टिक टॉक के संचालन वाले मूल एल्गॉरिद्म को भी हासिल करना चाहती थी।

ट्रंप के सत्ता में आने के बाद उन्होंने भी यही नीति जारी रखी और एक समयसीमा तय की कि कंपनी को या तो अपनी अमेरिकी संपत्तियों का स्वामित्व अमेरिकियों को सौंपना होगा, या फिर अमेरिका में अपना काम बंद करना होगा। चीन ने इस अमेरिकी कदम का विरोध किया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला दिया, जबकि चीन में खुद ऐसी स्वतंत्रता नहीं है।

विवाद के चलते चीन और अमेरिका ने कंपनी के भविष्य को लेकर बातचीत शुरू की। चीन ने टिक टॉक की अमेरिकी संपत्तियों को बेचने के विचार का विरोध किया, क्योंकि स्पष्ट रुप से वह अमेरिकी बाज़ार तक अपनी पहुँच खोने को लेकर चिंतित था।

दोनों देशों ने कंपनी के भविष्य को लेकर बातचीत जारी रखी, लेकिन ट्रंप की टैरिफ़ नीति के हमलों के बाद ये वार्ताएँ रुक गईं। बाद में जब चीन ने दुर्लभ खनिज जैसे अहम कच्चे माल की आपूर्ति रोकने जैसी गंभीर धमकियाँ दीं तो बातचीत फिर शुरू हुई।

अमेरिकी बाज़ार में टिकटॉक को बंद करने की धमकी देकर ट्रंप प्रशासन ने सीधे अमेरिकी स्वामित्व के तहत इसे चलाने की एक योजना तैयार की है।

भूपेन्द्र ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अनुभव है। वहीं, बिप्लब देब का अनुभव पूर्वोत्तर राज्यों से बंगाल की राजनीति को मजबूत करेगा।

बिहार के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी जबकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को सह-प्रभारी बनाया है।

तमिलनाडु में भाजपा सांसद बैजयंत पांडा को प्रभारी और मुरलीधर मोहोल को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है।

'बाँसवाड़ा की धरती पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- **प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को विकास की राह पर ले जाने में राजस्थान बड़ी भूमिका निभा रहा है।**
- **प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि प्र.मंत्री के नेतृत्व में राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान पर पहुँच गया है।**
- **कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने पं. दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने साफा पहनाकर और विजय स्तंभ का चित्र प्रदान कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया।**

सामर्थ्य का एक नया अध्याय लिखा गया है।

उन्होंने कहा कि देश में पूर्ववर्ती सरकारों ने बिजली के महत्व पर ध्यान नहीं दिया। आजादी के 70 साल बाद भी देश के 18 हजार गांवों में बिजली का खंभा तक नहीं लगा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार स्वच्छ ऊर्जा के अभियान को एक जन-आंदोलन बनाकर काम कर रही है। किसानों को सस्ती बिजली मिल सके, इसके लिए पीएम-कुसुम योजना के तहत खेतों में भी सोलर पंप लगाए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर उन्हें स्मरण करते हुए कहा कि उनका अंत्योदय का सिद्धान्त आज हमारा मिशन बन चुका है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ऊर्जावान नेतृत्व में राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। पीएम-कुसुम योजना के तीनों घटकों में राज्य में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। कुसुम योजना के घटक-ए में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है और राज्य के 22 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली मिलनी शुरू हो चुकी है।

मुख्यमंत्री ने 1 लाख 8 हजार करोड़ रुपये की ऐतिहासिक सौगातें राजस्थान को देने के लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 2 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी प्रतीक रूप में प्रदान किए। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस एवं उदयपुर सिटी-चंडीगढ़ एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। कार्यक्रम की शुरूआत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्व. पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का साफा पहनाकर और आदिवासी सम्मान का प्रतीक तीर-कमान भेंट कर स्वागत किया।

कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, सांसद मदन राठौड़, केन्द्र एवं राज्य सरकार के मंत्रीगण सहित, सांसद एवं विधायकगण और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

स्कूल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शर्त पर दी कि विद्यार्थियों को कोई असुविधा न हो।

उच्च न्यायालय ने स्कूल मैदान में रामलीला के आयोजन पर रोक लगा दी थी।

शीर्ष अदालत ने आदेश पारित करते हुए इस दलील पर भी गौर किया कि स्कूल के मैदान का उपयोग लगभग 100 वर्षों से रामलीला समारोहों समेत अन्य धार्मिक उत्सवों के लिए किया जाता रहा है।

पीठ ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, ''यह पिछले 100 सालों से होता आ रहा है। आपने आखिरी समय में अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया? आपको पहले से जाकर प्रशासन से व्यवस्था करने के लिए कहने से किसने रोका? आप न तो छात्र हैं और न ही किसी छात्र के अभिभावक... आप संपत्ति के मालिक नहीं हैं... आप जनहित याचिका दायर कर सकते थे, लेकिन आपको किसने रोका?''

सुप्रीम कोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खत्म करने के आदेश को बहाल कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए। अपीलकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट आर्यमा सुंदरम और गोपाल सुब्रमण्यम ने ये तर्क दिए: ओए की धारा 12 पहले केवल 7 वर्षों तक लागू थी। ज़मीन इतनी खराब थी कि वहाँ कुछ भी उगाना संभव नहीं था। पुर्तगाली प्रशासन ने खुद इन कठिनाइयों को मान लिया था।

सन् 1936 के पुर्तगाली डिक्री में कहा गया कि ऐसी ज़मीनें अहस्तांतरित हैं, और केवल सार्वजनिक कार्य या किराया न देने पर रद्द की जा सकती हैं।

हाई कोर्ट ने तथ्यों की दोबारा जांच करके धारा 100 सीपीसी के तहत अपनी सीमा का उल्लंघन किया।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कलैक्टर के फैसले का समर्थन किया और कहा, ओए की धारा 12 में स्पष्ट रूप से ज़मीन पर खेती करना अनिवार्य है और इस हल्का नहीं किया जा सकता।

पुर्तगाली कानूनों पर अपीलकर्ताओं की दलीलें पहले कभी निचली अदालतों में नहीं दी गई थीं, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार इन्हें उठाना स्वीकार्य नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सहमति जताई और कहा, ओए एक विशेष कानून है, जो दादर और नगर हवेली के लिए बनाया गया था और यह सामान्य पुर्तगाली भूमि कानून पर वरीयता रखता है। धारा 12 के तहत ज़मीन की रद्दीकरण प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से कलेक्टर द्वारा की जा सकती है, इसके लिए अलग से कानूनी कार्रवाई जरूरी नहीं। सरकारी नीति और सार्वजनिक हित में बनाए गए क़ानूनों की अवहेलना या माफ़ी नहीं दी जा सकती। सिर्फ राज्य की निष्क्रियता को मौन स्वीकृति नहीं माना जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें खारिज कर दीं और कहा कि सरकारी ज़िम्मेदारियाँ और वैधानिक शर्तें, चाहे वे औपनिवेशिक काल की विरासत ही क्यों न हों, उन्हें अनदेखा या माफ़ नहीं किया जा सकता।

अगले लोकसभा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुई ''सिंधु जल संधि'' एक ऐतिहासिक जल-बंटवारा समझौता था। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने यह संधि निलंबित कर दी थी, और सरकार ने दृढ़तापूर्वक स्पष्ट किया था कि ''पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते।''

तब से भारत सरकार सिंधु जल के अपने हिस्से के उपयोग के लिए एक विस्तृत योजना पर काम कर रही है। इसे साकार करने के लिए इंटर-बेसिन सिंधु जल ट्रांसफर योजना के तहत एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर विचार किया गया है, जिसकी निगरानी उच्च स्तर पर की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, इस परियोजना का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है- 14 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण। इसके लिए पर्वतीय चट्टानों का विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। यदि चट्टानें कमजोर पाई जाती हैं, तो सुरंग पाइपों के माध्यम से बनाई जाएगी। इसका निर्माण कार्य डीपीआर मिलने के बाद शुरू किया जाएगा।

सुरंग निर्माण के लिए ''टनल बोरिंग मशीन'' और ''रॉक शील्ड टैक्नॉलजी'' के उपयोग का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि गति और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जा सकें। यह सुरंग जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में स्थित ''उझ मल्टी परपज़ प्रोजेक्ट'' से भी जोड़ी जाएगी, जिससे रावी की सहायक नदी उझ से ब्यास बेसिन में जल स्थानांतरित किया जा सकेगा।

इस सुरंग के पूरा होने से रावी-ब्यास-सतलुज प्रणाली को सिंधु बेसिन से जोड़ा जा सकेगा, जिससे भारत अपने हिस्से के जल का अधिकतम उपयोग कर सकेगा। सूत्रों का अनुमान है कि इसका निर्माण तीन से चार वर्षों में पूरा हो जाएगा और यह कार्य 2028 तक तैयार हो सकता है। इसकी अनुमानित लागत करीब 4,000 - 5,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

MARUTI SUZUKI NEXA

CELEBRATIONS JUST GOT BIGGER.

WITH GST BENEFITS + LIMITED PERIOD FESTIVE OFFERS*

	PRICE REDUCTION OF UP TO#	NOW STARTING AT#	ADDITIONAL FESTIVE OFFERS OF UP TO*
FRONX	₹1 12 600	₹6 84 900	₹70 000
GRAND VITARA	₹1 07 000	₹10 76 500	₹1 29 100 + 5 Year Extended Warranty
BALENO	₹ 86 100	₹5 98 900	₹72 500
IGNIS	₹ 71 300	₹5 35 100	₹ 62 500
INVICTO	₹ 61 700	₹ 24 97 400	₹1 40 000
XL6	₹ 52 000	₹ 11 52 300	₹ 25 000
JIMNY	₹ 51 900	₹ 12 31 500	₹1 00 000

SCAN TO CONNECT TO A SHOWROOM NEAR YOU

NEXA SAFETY SHIELD

*FESTIVE OFFERS VALID TILL 30TH SEP ONLY

UP TO 100% WAIVER ON CAR LOAN PROCESSING FEE (ONLY TILL 30TH SEP)##

E-BOOK TODAY @ WWW.NEXAEXPERIENCE.COM

Contact us at 1800-200-[6392] 1800-102-[6392]

For detailed T&C kindly visit your nearest dealership. Features and accessories shown may not be a part of the standard fitment. Black glass shade on the vehicle is due to the lighting effect. Images used are for illustration purposes only. All offers are brought to you by NEXA dealers only. Offers and features may vary subject to the model and variant purchased. *The mentioned offers include "Consumer Offer + Booking offer + Exchange Bonus + Rural offer", and may vary from city to city. Please contact nearby dealership for more details. Maruti Suzuki reserves the right to withdraw offers at any point in time without any advance notice. All offers are applicable till 30th September '25 or till stocks last. Maruti Suzuki Smart Finance is now available pan India. Maruti Suzuki Subscribe is available only in selected cities. ##Offers include consumer offer, exchange bonus and institutional or rural offers (wherever applicable) on select models/variants. Finance is at the sole discretion of the financer by selected finance partners. #Prices and savings mentioned above are for select variants and may vary across cities/ variants.

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908